'श्रमेव जयते' पर प्रधानमंत्री जी को पाती

मोदी जी! हम कम पढे जरूर हैं, पर गधे नहीं हैं!

मननीय मोदी जी
नमस्कार!

हम एक कम पढे-लिखे मज़दूर हैं जो देश के एक छोटे से कारखाने में काम करते हैं। हम रोज सुबह 8 बजे काम पर जाते हैं और शाम को 8 बजे काम से आते हैं। कभी-कभी तो मालिक हमसे 4 घंटे ओवर टाइम लेकर 12 बजे ड्यूटी से छोड़ता है। अब इतना काम करने के बदले हम यही कोई 4-5 हज़ार कमा पाते हैं। अब ड्यूटी लम्बी हो जाती है कि घर में टीवी होने के बाद भी ठीक से देख नहीं पाते। ऊपर से मालिक की गाली-गलौच और जब देखो काम से निकालने की धमकी की वजह से हमेशा डर लगा रहता है कि रात को टीवी देखेंगे तो सुबह काम पर 10 मिनट भी लेट हो गये तो आधे दिन की दिहाड़ी कट जायेगी। इसी वजह से देश-दुनिया का इतना हाल कुछ पता नहीं रहता पर इतना जरूर जानते हैं कि कुछ महीने पहले देश का राजा मनमोहन सिंह से बदलकर आप बन गये हो। यह भी जानते हैं कि आप भाषण बहुत अच्छा देते हो। राहुल तो आपके आगे कहीं टिकता ही नहीं था। हम खुद आपको कभी सुने नहीं हैं पर आते-जाते लोग आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं।

वह तो गनीमत थी कि अबकी बार 15 अगस्त को हमारी फैक्ट्री में नये काम का आर्डर ही नहीं था, इसलिए उस दिन मालिक फैक्टरी बंद कर दिया पर साथ ही दिहाड़ी भी काट लिया। वरना हर वर्ष तो क्या 15 अगस्त क्या 26 जनवरी हर दिन काम पर दौड़ना पड़ता था। सो अबकी 15 अगस्त को हम घर पर थे। हमारा बच्चा फ़िल्म देखने की जिद कर रहा था पर हमने कहा कि हम मोदी जी का लालकिले से भाषण सुनेंगे।

सो हमने पहली बार टीवी पर आपका भाषण सुना जब भाषण में आपने कहा कि कुछ दिनों बाद आप मज़दूरों के लिये भी एक योजना शुरू करेंगे तो हम बहुत ही खुश हुए कि चलो किसी राजा को हमारा ख्याल तो आया कि अब हमारे दिन भी सुधरेंगे।

अगली बार जब फैक्टरी में हमारे सुपरवाइजर ने हमको गाली दिया तो हम उसको बोले कि अब और ज़्यादा दिन हम गाली नहीं खायेंगे। देश का राजा हमारे लिए सोचता है और हमारे लिए स्कीम लाने वाला है। तो सुपरवाइजर हंसते हुए बोला कि, ''कोई भी स्कीम आ जाये तुम गाली ही खाओगे''।

खैर हमने सोच लिया था कि जिस दिन स्कीम शुरू होगी उस दिन हम छुट्टी लेकर आपका भाषण सुनेंगे। सो जब खबर चली कि आप कल मज़दूरों की योजना शुरू करेंगे तो हम अपने दो साथियों के साथ छुट्टी ले टीवी के आगे जम गये।

पहले जब टीवी पर बताया गया कि योजना 'श्रमेव जयते' होगी तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समाये कि अब तो 'श्रमेव जयते' यानि मज़दूर ही जीतेगा। यानि सुपरवाइजर-मालिक इन दोनों से मज़दूर ज्यादा ऊंचा होगा और अब सुपरवाइजर हमको गाली तो नहीं ही दे पायेगा। खैर! जब टीवी पर बताया गया कि योजना किसी दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चलायी जा रही है तो हम सोचे की ई जरूर कोई मज़दूर का बड़ा नेता होगा। हमारी फैक्ट्री में भी दो उपाध्याय काम करते हैं पर तभी हमारे साथ का मज़दूर बोला कि ये कोई मज़दूरों के नेता नहीं मोदी की पार्टी के पुराने नेता थे। साथी मज़दूर चूंकि बी.ए. पास था। इसलिए उसने दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुना था। हमें दुख तो हुआ कि मज़दूरों की योजना तो मज़दूरों के नाम पर चलाते खैर कोई बात नहीं।

जब आप मंच पर आये और बोले कि 'श्रमेव जयते' 'सत्यमेव जयते' की तरह ही होगा तो हम बड़े खुश हुए कि हिन्दी फिल्मो में जैसे अन्त में सत्य जीतता है वैसे ही अब अपनी जिन्दगी की फ़िल्म में मज़दूर जीतेगा। इससे पहले आपके श्रम मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मज़दूरों को प्रशिक्षित किया जायेगा, नये आईटीआई खुलेंगे और अप्रेंटिस एक्ट पास होने पर नये रोजगार पैदा होंगे तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया पर बुरा भी नहीं लगा कि वह मज़दूरों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं।

आपके भाषण के शुरूआती हिस्से में जब कहा गया कि हमें शारीरिक श्रम को नीची निगाहों से देखना बंद करना होगा। सभी समस्याओं को मज़दूरों की नजर से देखना होगा तो हम बहुत खुश हुए। इसके बाद आपने एक पीएफ़ अकाउंट नम्बर देने की बात शुरू की और किसी वेबसाइट पर सारी सूचना मिलने की बात की तो हमने सोचा कि ये पीएफ़ हमारा तो कटता नहीं पर हमारी फैक्टरी के कुछ परमानेंट मज़दूरों का कटता है। चलो उनका कुछ तो भला होगा। हम सोचे कि आप हमारे बारे में आगे बात करोगे।

पर इसके बाद आप जो बोले वह कुछ इस तरह था कि हमारे देश में मज़दूर तो हैं पर प्रशिक्षित नहीं हैं। देश में बाहर की कम्पनियां लाकर 'मेक इन इंडिया' सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित मज़दूर जरूरी हैं। साथ ही देश में ढ़ेरों श्रम कानून हैं जो कंपनियों को आने से रोकते हैं इसलिए अब लाइसेंस राज खत्म करना है। अब कंपनी मालिक खुद ही श्रम कानून के पालन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हम देश के नागरिकों पर भरोसा करते हैं इसलिए अब मालिक खुद ही कानून लागू करेंगे, कोई इंस्पेक्टर, उन्हें तंग नहीं करेगा। इसके बाद आपका भाषण खत्म हो गया।

अपने फ़ायदे की बात सुनने को बैठे हम तीनों मज़दूरों को आपकी ये बातें सुनकर सांप सूंघ गया। हमें लगा कि आपमें हमारे मालिक की आत्मा प्रवेश कर गयी है। वैसे हमारे यहां लेबर इंस्पेक्टर कभी-कभी आता है पर जब आता है मालिक 8 घंटे में ही हमारी छुट्टी कर देता है सो हम ऊपर वाले से मनाते हैं कि ये इंस्पेक्टर रोज आये। पर आप तो इंस्पेक्टर राज खत्म कर मालिकों को खुली छूट दे दिये हो। हम तो इंस्पेक्ट के पास इकट्ठा हो 8 घंटे काम, दुगुने ओवर टाइम, न्यूनतम मज़दूरी न मिलने की शिकायत के साथ मालिक की गाली-गलौच की शिकायत करने वाले थे पर आप तो श्रम विभाग ही खत्म करने पर उतारू हो। यह कौन सा समस्या को मज़दूरों के पक्ष से देखने का नजरिया है। यह तो खुल्लम-खुल्ला मालिकों के फ़ायदे और मज़दूरों के नुकसान की स्कीम है।

आपको देश के नागरिकों पर नहीं देश के मालिकों पर भरोसा है। नागरिक तो हम भी हैं और संख्या में मालिकों से ज़्यादा हैं। ईमानदारी की बात तो यह होती कि श्रम कानून लागू करने का सर्टिफिकेट देने का ज़िम्मा आप मज़दूरों को दे देते पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने मालिकों पर भरोसा किया और हम समझ गये कि आप भी पहले के राजाओं की तरह पैसे वालों के ही आदमी हो। 'श्रमेव जयते' मज़दूरों की जीत नहीं मज़दूरों की लूट बढ़ाने की स्कीम है।

मोदी जी, हम अनपढ जरूर हैं पर गधे नहीं। हम सीधे सादे हैं। जो दिल में होता है वही कहते हैं पर आप तो बड़े फ़रेबी हो। पहले चिकनी-चुपड़ी बातें कर बाद में छुरा भोंकते हो। आप सीधे कह देते कि मालिकों के लिए नयी स्कीम लागू करेंगे तो हम कम से कम एक दिन की छुट्टी कर दिहाड़ी तो न गंवाते। हम सीधी बात कहते हैं मोदी जी मज़दूर गधे नहीं है बस थोड़े बंटे हुए हैं और जिस दिन वे एक हो जायेंगे उस दिन वे मालिक-सुपरवाइजर तो क्या आप जैसे राजा से भी निपट लेंगे और हां वह इसके लिए आपकी तरह फरेब नहीं करेंगे। आप चाय बेचने वाले की दुहाई दे जीतकर मालिकों की सेवा कर मज़दूरों से गद्दारी कर सकते हो पर मज़दूर वर्ग आपको इस गद्दारी की सज़ा जरूर देगा।

खैर हमारी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करें। हां आपका भाषण सुनने से इतना लाभ तो जरूर हुआ कि आगे से कभी आपका भाषण सुनने को हम दिहाड़ी नहीं खोयेंगे।

-आपके देश का एक मज़दूर

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 16 से 30 नवम्बर 2014 के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। लेख ''जब जेई रामपाल काबू नहीं आया तो 'संत' रामपाल तुम्हें औकात दिखायेगा ही'' तथा 'भस्मासुर ऐसे ही बनते आए हैं-हत्यारोपी बाबा के दरबार में 35 विधायक पहुंचे मत्था टेकने' द्वारा राजसत्ता व धर्म सत्ता के बीच गठजोड़ का पर्दाफ़ाश किया गया है।

प्राचीन काल से ही धार्मिक गुरू राजा की सत्ता स्थापित रखने के लिये राजा के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे हैं और राजा उनको संरक्षण प्रदान करता रहा है। जनता में राजा का औचित्य, भय व आदर बनाए रखने के लिये स्मृतियों व नीति शास्त्रों की उनके द्वारा रचना की गई। परंतु जब भी दोनों में से किसी ने अपनी-अपनी सीमाएं लांघने अथवा एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की तो आपस में झगड़ा भी हुआ। यदि उनमें से एक कमज़ोर हो गया अथवा दूसरे के हितों का विरोधी हो गया तो दूसरे ने उसकी हत्या करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है। सत्ता प्राप्त करने के लिये राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और इसके लिये उन्हें लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है।

प्रजातंत्र में धर्म और राजनीति का आपस में घालमेल होने की बजाए उन्हें अलग-अलग रखना चाहिए। परंतु जिन राजनीतिक दलों के पास लोगों को अपने साथ जोड़ने और उनके विकास के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं होता वे धर्म का सहारा लेते हैं। ये तथाकथित धार्मिक बाबा अपने अनुयायियों से किसी विशिष्ठ राजनीतिक दल के पक्ष में वोट दिलाने में सहायता करते हैं तो बदले में राजतनीतिक दल उनको राजनीतिक व कानूनी आश्रय प्रदान करते हैं।

कालांतर में ये धार्मिक संस्थान राजसत्ता का समानांतर केंद्र बन जाते हैं जो राजसत्ता को चुनौती देने में सक्षम हो जाते हैं और अदालत, कानून, पुलिस व सरकार की कोई परवाह नहीं करते। इसलिए धार्मिक गुरूओं व राजसत्ता में टकराव होता रहा है, जिसके उदाहरण हैं 'संत' आसाराम, बाबा रामदेव, सच्चा सौदा डेरा के राम रहीम, द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सरूपा नंद, चंद्रा स्वामी उर्फ नेमी चंद, 'संत' भिंडरावाला आदि। लेकिन पुलिस, प्रशासन, अदालत व कानून को खूलेआम चुनौती देने की हिसार में बरवाला के विवादित संत रामपाल की महत्वपूर्ण घटना है। वास्तव में रामपाल का आश्रम नहीं बल्कि एक मज़बूत किला है। इसको बनाने में हरियाणा की सरकारों ने ही विभिन्न प्रकार की सहायता दी होगी वरना यह किला नुमा आश्रम तथा सत्ता का समानांतर क्रेड नहीं बन सकता था।

पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकार ने रामपाल को गिरफ़्तार करने में देरी की। आश्रम में कितने लोग थे तथा कितने व किस प्रकार के हथियार व रामपाल के कमांडों मौजूद थे इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले में सरकार की जासूस व्यवस्था बेकार साबित हुई।

आरोप है कि पुलिस ही मीडिया को आश्रम के पास स्वयं लेकर गई और फ़िर पुलिस ने ही इन मीडिया कर्मियों पर आक्रमण कर दिया, यह एक निंदनीय कार्य था। पुलिस का भारी दल-बल वहां मौजूद था परंतु तुरंत कार्यवाही न करने से रामपाल व उसके सुरक्षा कर्मियों का साहस बढ गया। आरोप लगाया जाता है कि रामपाल ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट दिलाने में सहायता की थी। सच्चा सौदा डेरा के राम रहीम व बाबा रामदेव ने तो खुलकर लोकसभा व हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा की सहायता की थी। उन धार्मिक गुरूओं को खुश व संतुष्ट रखने के लिये उनकी विभिन्न शर्तों को सत्ता द्वारा पूरा भी किया जाता है, अन्यथा उनमें टकराव की स्थिति आएगी ही। इसलिए हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 47 में से 35 विधायक पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में हाई कमांड के आदेश पर बाबा राम-रहीम के सिरसा स्थित दरबार में मत्था टेकने गए। वहां उनमें आपस में क्या सौदेबाज़ी हुई यह गोपनीय है। बाबा रामदेव कहीं रामपाल की तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा की चुनौती न दे दे इसलिए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करके संतुष्ट रखने की कोशिश की।

सुरक्षा के नाम से रामदेव की निजी व सार्वजनिक गतिविधियों पर सरकार की निगरानी का शिकंजा कस दिया गया जिससे कि रामदेव कभी राजसत्ता को चुनौती न दे सके। इन सबके बावजूद राजसत्ता द्वारा पोषित धार्मिक गुरूओं व राजसत्ता के बीच कब टकराव हो जाए पता नहीं।

लेख 'असली दामाद तो आप सभी का डी एल एफ़ है खट्टर जी!' द्वारा राबर्ट वाड्रा तथा भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध कार्यवाही का चुनावी मुद्दा बनाने के बावजूद मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करने का ठीक मुद्दा उठाया गया है। इस मामले में लगातार हो रही आलोचना के कारण मज़बूर होकर खट्टर सरकार ने गुड़गांव, फ़रीदाबाद मेवात व पलवल ज़िलों के उपायुक्तों से वाड्रा-डी एल एफ डील के बारे में पूरा रिकार्ड मांगा है। रिकार्ड मांगने की कार्यवाही कहीं कोरी लीपा-पोती न रह जाए, यह भविष्य में पता लगेगा।

'पीपी:यानी पाखंडी प्रधानमंत्री', 'रंगीला प्रधानमंत्री', 'मोदी का विकल्प क्या?', 'विकास के गुजरात मॉडल का सच', 'मोदी संदेश: 'जो कुछ भी करेंगे निडरता से डंके की चोट पर करेंगे' व 'मोदी को सम्बोधि' लेखों के ज़रिए प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, मार्केटिंग करने की कुशलता, प्रचार शैली तथा सब्ज़बाग दिखाकर जनता को लुभाने की कला का सांगोपांग विश्लेषण किया गया है। अन्य प्रकाशित लेख भी प्रशंसनीय व प्रेरणादायक हैं।

तुर्की-ब-तुर्की

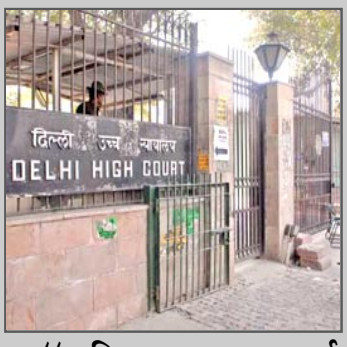

''यदि 60 000 सफ़ाई कर्मचारी दिल्ली को साफ़ नहीं रख सकते तो उन्हें घर बैठा देना चाहिये।'' (दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिविजन बैंच ने दिल्ली में सफ़ाई की स्थिति पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की)

हमारा कहना है:-

- दिल्ली में जगह-जगह गंदगी के ढेर वास्तव में किसी के भी धैर्य की परिक्षा ले सकते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि यदि तमाम सफ़ाई कर्मचारी अपना कार्य न कर रहे होते तो दिल्ली स्वयं एक कूड़े का ढेर होती।
- हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि मोदी सरकार का समूचा सफ़ाई अभियान नये-नये झाड़ू पकड़कर फ़ोटो खिंचवाने तक ही सीमित है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय का सफ़ाई सरोकार भी, जो वातानुकूलित अदालती कक्षों में व्यक्त किया जा रहा है, वास्तविक सफ़ाई में कोई योगदान नहीं देता। सफ़ाई तो अन्ततः सफ़ाई कर्मचारियों को ही करनी होती है जिसे वे भरसक कर भी रहे हैं।
- कुछ इलाकों में सफ़ाई में देरी या कोताही का अर्थ यह नहीं कि सफ़ाई कर्मचारी निकम्मे हैं। इसकी असली वजह यह है कि उन्हें वह सुविधा और साजो-सामान नहीं दिये गये जो सफ़ाई के लिये आवश्यक हैं। और ना ही सफ़ाई के काम का आधुनिकीकरण ही किया गया है। यहां तक कि सीवर, ड्रेन इत्यदि के निर्माण में भयानक घपलेबाज़ी का बोझ भी इन्हीं के सिर पर पड़ता है। ऐसे में अकेले सफ़ाईकर्मियों को इंगित करना हाई कोर्ट की अभिजात दृष्टि का नमूना है न कि न्याय दृष्टि का।
- देरी और कोताही तो न्यायपालिका का भी अभिन्न हिस्सा हैं। बरसों-बरसों तक मुकदमों के फ़ैसले नहीं होते। यहां तक कि बेगुनाह बरसों तक जेलों में सड़ते रहते हैं। छोटे-मोटे झगड़े भी त्वरित न्याय के अभाव में गंभीर मामलों और हत्या तक पहुंच जाते हैं। तो क्या जजों को घर नहीं बैठा देना चाहिये?